ट्रम्प कैनडा व मैक्सिको पर भारी आयात शुल्क लगाएंगे, भारत को नए अवसर मिलेंगे

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 29 नवम्बर। अगले साल 20 जनवरी को डॉनल्ड ट्रम्प वाइट हाउस में चले जाएंगे और उनके द्वारा तुरंत लिया जाने वाला एक निर्णय होगा कैनडा और मैक्सिको से आयात पर शुल्क लगाना।

यह प्रस्तावित कदम भारत के लिए, बढ़े हुए व्यापार, निवेश और बदले हुए सप्लाई चेन के माध्यम से अवसर पैदा करेगा।

- ट्रम्प ने शपथ ली है कि वाइट हाउस जाने के साथ ही वे पहला निर्णय कैनडा और मैक्सिको पर आयात शुल्क लगाने का करेंगे।
- विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत के लिए व्यापार, निवेश के नए अवसर खुलेंगे तथा टैक्सटाइल, इलैक्ट्रॉनिक्स और कैमिकल उद्योग में भारत को भारी लाभ हो सकता है।
- विशेषज्ञों ने कहा कि अगर आयात शुल्क के दायरे में कृषि उत्पादों को भी शामिल किया जाता है तो भारत को दालें, मसाले व प्रौसैस्ड फूड के निर्यात का भी अवसर मिलेगा।

व्यापार विश्लेषकों का कहना है कि यदि अमेरिकी कम्पनियों को कैनडा और मैक्सिको से आयातित माल पर लगाए गए शुल्क के कारण ऊँची लागत का सामना करना पड़ता है, तो वे वैकल्पिक सप्लायर्स की तलाश कर सकते हैं। अपनी बेहतर उत्पाद क्षमता के साथ भारत, विशेष रुप से वस्त्र, दवा और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में माल की आपूर्ति करने के लिए आगे आ सकता है।

यदि ये शुल्क कृषि उत्पादों पर भी लागू होते हैं, तो भारत को अमेरिका के बाज़ार में अनाज, मसाले और प्रोसैस्ड खाद्य पदार्थ निर्यात करने का अवसर मिल सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि भारत के लिए टैक्सटाइल, इलैक्ट्रॉनिक्स और कैमिकल्स जैसे उद्योगों को टारगेट करना विशेषरुप से लाभकारी होगा।

कैनडा या मैक्सिको की कंपनियाँ, जो अमेरिका के साथ व्यापार पर निर्भर हैं, वो अपना कामकाज ऐसे देशों में ले जाने के बारे में सोच सकती हैं जहाँ व्यापार में बाधाएं कम हों। एक बढ़ती इकॉनमी के रुप में भारत, जहाँ व्यापार के क्षेत्र में अनुकूल सुधार हुए हैं, ऐसे कुछ निवेशों को आकर्षित कर सकता है।

इसके अलावा अमेरिका, भारत को उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक विकल्प के रुप में देख सकता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका के उद्योगों को शुल्कों से प्रभावित होकर उच्च लागत का सामना करना पड़ता है, तो वे अन्य क्षेत्रों में खर्चों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जिससे, इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलजी, व्यापार प्रक्रियाएं तथा अन्य सेवाएं भारतीय कंपनियों को आउटलोर्स करने की सोच सकते हैं।

इसके साथ-साथ, कैनडा और मैक्सिको के साथ तनावपूर्ण रिश्तों से उत्पन्न होने वाले परिणामों को संतुलित करने के लिए अमेरिका, भारत के साथ नजदीकी संबंध बनाने पर विचार कर सकता है। इससे टैक्नॉलजी और डिफैन्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार समझौतों या सहयोग की संभावना हो सकती है।

अमेरिका के इस कदम से लाभ उठाने के लिए भारत को कई चुनौतियों का सामना करना होगा। भारतीय उत्पादों को अमरीकी गुणवत्ता तथा नियामक मानकों पर खरा उतरना होगा, ताकि इन अवसरों का पूरा लाभ उठाया जा सके। इस स्थिति से लाभ उठाते हुए, भारत को अपनी कूटनीति पर चलते हुए भी सावधानी बरतनी होगी, ताकि सभी संबंधित देशों के साथ मजबूत संबंध बने रहें।

इसके अतिरिक्त, व्यापार विश्लेषक कहते हैं कि चीन द्वारा भारत को दी जा रही प्रतिस्पर्धा को किसी भी स्थिति में नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता।

नॉर्थ अमेरिका में बनी वस्तुओं पर शुल्क लगाने से, अमेरिका की कंपनियाँ, अन्य क्षेत्रों से अधिक किफायती वस्तुओं की सोर्सिंग करने पर विचार कर सकती हैं। जिससे, पहले से लागू शुल्क के बावजूद, चीन के मैनुफैक्चरिंग सैक्टर को लाभ हो सकता है। चीन में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तथा इसकी सप्लाई चेन मजबूत है, जिसके कारण चीन कैनडा और मैक्सिको द्वारा खाली छोड़े गए स्थान को भरने के लिए एक मजबूत दावेदार बन सकता है। हालाँकि, चीन में होने वाला अत्यधिक उत्पादन तथा वर्तमान में कमज़ोर पड़ी उपभोक्ता मांग, जैसी चुनौतियाँ इस देश को इन बदलावों का पूरा लाभ उठाने में बाधा बन सकती हैं।

भारत के लिए, यह स्थिति "चाइना प्लस वन" रणनीति को मजबूत करने का अवसर देती है, जिसका उद्देश्य निर्माताओं को चीन से अलग होने के लिए आकर्षित करना है। अब जबकि, ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स बदल रहे हैं, तो ऐसे में भारत खुद को एक "वैकल्पिक मैनुफैक्चरिंग हब" के रुप में प्रस्तुत कर सकता है। खासकर, अगर भारत घरेलू उत्पादन को सहायता देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी नीतियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा कर उनकी कार्यप्रगति की जानकारी ली तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

'जयपुर को ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रभावी योजना बनायें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने नगरीय विकास की समीक्षा में कलैक्ट्रेट सर्किल व गाँधीनगर मोड़ के लिये निर्देश दिये

- मुख्यमंत्री ने बैठक में रिद्धी-सिद्धी फ्लायओवर, इमली वाला फाटक फ्लायओवर, सांगानेर में एलिवेटिड रोड, सिविल लाइन्स रोड ओवर ब्रिज, गॉल्फ क्लब पार्किंग, जयपुर मेट्रो विस्तार, रिंग रोड आदि की प्रगति की जानकारी ली।
- बैठक में जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मंडल, मुख्य नगर नियोजक सहित नगरीय विकास, विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के भी निर्देश दिये गये।

जयपुर, 29 नवंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के लिए कहते हुए कहा कि बढ़ती आबादी के चलते जयपुर में यातायात भार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्र का ट्रैफिक प्रबंधन बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए, खासतौर पर कलैक्ट्रेट सर्किल और गांधीनगर मोड़ के लिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक डाइवर्ज़न के लिए वैकल्पिक मार्गों का भी विकास किया जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शहरी बुनियादी ढ़ांचे को विश्वस्तरीय बनाने एवं जनसुविधाओं को सशक्त एवं समावेशी बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को दी जा रही सेवाओं के स्तर को बेहतर बनाया जाए तथा नगरीय विकास के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाए, ताकि शहरी विकास के नए आयाम स्थापित हो सके।

मुख्यमंत्री शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित नगरीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया और उन्होंने बजट में विभागीय घोषणाओं की समीक्षा कर उनकी कार्यप्रगति की जानकारी ली तथा उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने रिद्धी-सिद्धी फ्लाईओवर, इमलीफाटक फ्लाईओवर, सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पम्प तक एलिवेटेड रोड, सिविल लाइन्स आरओबी, रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग की प्रगति की जानकारी ली तथा इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने द्रव्यवती नदी का सौन्दर्यीकरण, आई.पी.डी. टावर के निर्माण, जयपुर मेट्रो के विस्तार, रिंग रोड़ के निर्माण, आर.ओ.बी. (रोड ओवर ब्रिज), आर.यू.बी. (रोड अंडर ब्रिज), सेक्टर रोड, ऐलिवेटेड रोड सहित विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड का मुख्य काम आमजन को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ऐसे में मण्डल अपनी आवासीय योजनाओं की गति में तेजी लाएं। साथ ही, मण्डल की सभी सम्पत्तियों का विवरण ऑनलाइन हो, ताकि लोगों को इनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि नई आवासीय योजनाओं में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, साथ ही ऑनलाइन आवेदन तथा ई-नीलामी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जाए।

शर्मा ने अधिकारियों को जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन मण्डल, मुख्य नगर नियोजक सहित, नगरीय विकास विभाग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरीय विकास विभाग द्वारा जल्द से जल्द अपने अभियान्त्रिकी संवर्ग के सेवा नियम बनाए जाएं, जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र नवीन पदों पर भर्ती की जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन विभागों में लम्बे समय से एक स्थान पर कार्यरत कार्मिकों को बदला जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कार्मिकों को नहीं बख्शा जाएगा तथा ईमानदार कार्मिक को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में कार्मिकों से संबंधित सभी लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें। बैठक में शहरी परिदृश्य एवं नगरीय निकायों की स्थिति, विभागीय महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, नवाचारों, मास्टर प्लान एवं ज़ोनल डवलपमेंट प्लान की स्थिति सहित विभिन्न विभागीय बिन्दुओं पर चर्चा की गई।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया ने प्रैजेन्टेशन के माध्यम से नगरीय विकास विभाग के कार्यक्रमों, नवाचारों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बांग्लादेश में हिंदुओं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इस्कॉन के प्रमुख हैं।

चिन्मय दास को जमानत नहीं दी गई है, वे अभी भी जेल में ही हैं। उन पर देशद्रोह तथा बांग्लादेश के झंडे का अपमान करने का आरोप है। भारत का कहना है कि चिन्मय कृष्णदास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए। यह यकीन करने के पूरे कारण हैं कि अल्पसंख्यकों पक्ष रख रहे चिन्मय कृष्ण दास पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। हाल ही में, बांग्लादेश में भारतीय झंडे का अपमान करने की कई घटनाएं हुई हैं, एक कट्टरपंथी संगठन के सदस्यों ने यह हरकत की है।

आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा है, जबकि वे तो हर छोटी बात पर टीका टिप्पणी करने के लिए जानी जाती हैं। हिंदुओं के खिलाफ हो रहे संगठित हमले पर वे चुप है इससे पहले भी जब शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद हुई हिंसा पर भी चुप रही। इसी बीच, शेख हसीना ने अवश्य हालिया घटनाओं पर टिप्पणी की तथा हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की।

पहली बार के सांसद मुरलीधर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

132 सीटों के साथ भाजपा सबसे आगे है। पर अभी भी भाजपा ने विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणा होनी है।

पूरी संभावना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा को ही मिलेगी, क्योंकि इसकी सीटें सर्वाधिक हैं। शिंदे की शिवसेना को 57 और अजित पवार की एन. सी. पी. को 41 सीटें मिली हैं। ये दोनों दल मुख्यमंत्री की कुर्सी की बजाय प्रमुख विभागों पर फोकस कर रहे हैं।

शिंदे ने अपनी पार्टी के नेताओं को संकेत दिया है कि वे उपमुख्यमंत्री का पद नहीं लेगें, क्योंकि यह उनका डिमोशन होगा, इसलिए उनकी पार्टी का कोई और नेता उपमुख्यमंत्री बनेगा।

सूत्रों ने संकेत दिया कि नई सरकार के पावर शेयरिंग फॉर्मूला में दो उपमुख्यमंत्री होंगे, एक भाजपा से तथा दूसरा घटक दलों से। मंत्री पदों के वितरण में भाजपा 20 विधायकों को मंत्री बनाएगी, जिनमें एन. सी. पी. की बजाय शिवसेना से ज्यादा मंत्री लिए जाएंगे।

इसी बीच, शिवसेना नेता दृढ़ता से कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनका कहना है कि महायुति को यह जीत शिंदे की "लड़की बहिन" योजना की सफलता से मिली है।

इस समय शिंदे के अगले कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी प्रवक्ता और विधायक संजय शिरसत ने कहा कि शिंदे के उपमुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने की संभावना नहीं है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, उसके लिए उपमुख्यमंत्री बनना सही नहीं है। इसके अनिश्चितता और बढ़ गई है।

सिरसत ने कहा कि शिंदे की चिंता यही है कि पार्टी के कई नेता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली मूल शिवसेना में लौट सकते हैं, जिससे उनकी सौदेबाजी करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे, जो कल्याण से सांसद हैं, ने कहा कि उनके पिता महायुति के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उनकी प्राथमिकता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बजाय सामूहिक शासन है, वे गठबंधन धर्म को प्राथमिकता देते हैं। ऐसा कहकर श्रीकांत ने अटकलों को विराम देने का प्रयास किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, अगर भाजपा मुरलीधर को चुन ले जो दूर-दूर कहीं भी रेस में नहीं हैं। पार्टी ने राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में ऐसा ही किया था।

क्या एकनाथ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पवार ग्रुप के लिए क्रमशः 11 और 9 विभाग छोड़ना चाहती है। कथित रूप से वित्त विभाग अजित पवार ग्रुप के पास ही रहेगा, जबकि शिंदे सेना को शहरी विकास तथा जन कल्याण विभाग मिलेंगे। शिंदे सेना प्रवक्ता, संजय शिरसाट ने महायुति में चल रही आंतरिक कशमकश के संकेत दिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री रह चुका हो उसके लिए उपमुख्यमंत्री के रूप में पद स्वीकार करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा "लेकिन, शिंदे साहब से हमारी प्रार्थना है कि उन्हें केन्द्र में नहीं जाना चाहिए। तथापि, जो भी निर्णय वो लेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे।"

गुरुवार की शाम को अमित शाह से मीटिंग के बाद, जिसे उन्होंने सकारात्मक बताया, शिंदे संभवतः दिल्ली जाने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे भी, उनके पार्टी नेता, इन संभावनाओं को लेकर आशान्वित हैं कि, भाजपा शायद एक बार फिर मुख्यमंत्री का पद शिंदे को दे देगी। लेकिन, ये संभावनाएं मूर्तरूप लेंगी, इसके आसार कम हैं। तथापि, शिरजाट ने कहा, "पहले मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय हो जाने दें। बाकी बाद में होगा।"

सी.डब्ल्यु.सी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जो इस बिन्दु पर अन्दरूनी अभिशंसाएं देंगी कि संगठन आगामी चुनाव लड़ने के लिये चुस्त-दुरूस्त कैसे बने।

खड़गे ने कहा कि पार्टी को कुछ सख्त निर्णय लेने की जरूरत है तथा आगामी दिनों और सप्ताहों में ऐसा किया जायेगा।राहुल ने गौरव गोगोई की इस बात का समर्थन किया कि अगर पार्टी गलत कामों को लेकर सेबी से टक्कर ले सकती है तो चुनाव आयोग से, उसकी कमियों और खामियों को लेकर, क्यों नहीं टकरा सकती। अब तक पार्टी चुनाव आयोग के साथ नरमी से पेश आती रही है, भले ही वह पूरी तरह से पक्षपात करता रहा हो।

सी.डब्ल्यू.सी. ने साम्प्रदायिकता तथा विभाजनकारी नीतियों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला तथा कहा कि सरकार सत्ता की सतत भूख के कारण, संस्थाओं तथा तंत्रों को नष्ट कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था कि उस जगह पहले हरिहर मन्दिर बना हुआ था।

चौबीस नवम्बर को इसका विरोध करने के लिये लोग मस्जिद के पास इकट्ठे हो गये तथा सुरक्षाकर्मियों के साथ उनका टकराव हो गया तथा इसके बाद पत्थरबाजी तथा आगजनी की गई। हिंसा में चार लोग मारे गये तथा अन्य बहुत से लोग घायल हो गये।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देशों के जरिये, इस मामले में ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हस्तक्षेप किया है, जब दक्षिणपंथी हिन्दुत्ववादी ग्रुप बड़ी संख्या में स्थानीय अदालतों में पहुँच रहे थे तथा कह रहे थे कि यह मालूम करने के लिये सर्वे के आदेश दिये जायें कि यह मन्दिर है या मस्जिद है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का स्वागत करते हुये, सर्वोच्च न्यायाल के वरिष्ठ एडवोकेट प्रशान्त भूषण ने "एक्स" पर टिप्पणी की है: "सर्वोच्च न्यायालय ने सम्भल की मस्जिद के सर्वे के प्रकरण में ट्रायल कोर्ट को यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देकर सराहनीय कार्य किया है। ऐसी आशा है कि इससे वहाँ हो रहा अनिष्ट रूक जायेगा। आशा की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय जल्दी ही उन साम्प्रदायिक उपद्रवों का अन्त कर देगा, जो पूरे देश में मस्जिदों के सर्वे की आड़ में हो रहे हैं।"

दुष्कर्म के प्रयास ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसमें ए.डी.जे. कोर्ट ने 18 दिसंबर, 1991 में याचिकाकर्ता को पांच साल की सजा सुनाई थी। मामले में पीड़िता के अलावा, कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं था। इसके अलावा मेडिकल में पीड़िता के चोट भी नहीं मिली। वहीं, सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता मानवेन्द्र सिंह ने कहा कि एफ.एस.एल. जांच में दुष्कर्म का प्रयास साबित है।

राजस्थान की सड़कों के लिए केन्द्र ने 1154 करोड़ की मंज़ूरी दी

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरूवार को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी

- केन्द्र सरकार ने यह राशि केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधी (सी.आर. आई.एफ.) तथा सेतुबंधन योजना के तहत स्वीकृत की है।

जयपुर , 29 नवम्बर। प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1154.47 करोड़ रूपये की तथा श्रीगंगानगर में रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण के लिए 30 करोड़ रूपये स्वीकृति दी है। इस राशि से राज्य की 748.80 कि.मी की सड़कों का चौड़ाई करण एवं सुदृढ ीकरण तथा कोटा में कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयासों से केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सी.आर.आई.एफ.) से राज्य सड़कों के विकास के लिए तथा सेतु बंधन योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा यह राशि स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से न केवल परिवहन सुगम होगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

प्रदेश के 15 लोकसभा क्षेत्रों के 17 जिलों में इस राशि से वृहद जिला सड़क (एम.डी.आर.) तथा स्टेट हाईवे श्रेणी की 27 सड़क परियोजनाओं का चौड़ाई करण एवं सुदृढ़ ीकरण किया जाएगा।

इस राशि से अलवर लोकसभा क्षेत्र के अलवर जिले में 24 करोड़ की लागत से 24 कि.मी,खैरथल-तिजारा जिले में 69 करोड़ की लागत से 51 कि.मी, कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 49.30 करोड़ की लागत से 28.62 कि.मी, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बालोतरा जिले में 57.50 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, भीलवाड़ा के शाहपुरा जिले में 74 करोड़ की लागत से 44 कि.मी, बीकानेर जिले में 73.30 करोड़ की लागत से 71.80 कि.मी, चित्तौडगढ के प्रतापगढ जिले में 20 करोड़ की लागत से 17 कि.मी,जयपुर ग्रामीण तथा सीकर लोकसभा क्षेत्र के जयपुर ग्रामीण में 65 करोड़ की लागत से 57.70 कि.मी सड़कों का निर्माण चौड़ाईकरण एवम सुदृढ़ ीकरण करवाया जाएगा।

इसी प्रकार जालौर में 65 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, झालावाड़ जिले में 149.97 करोड़ की लागत से 81.25 कि.मी,जोधपुर के फलौदी जिले में 55.65 करोड़ की लागत से 53 कि.मी,कोटा के बूंदी जिले में 80 करोड़ की लागत से 33 कि.मी तथा कोटा में 70 करोड़ की लागत से कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण,पाली के जोधपुर ग्रामीण में 98 करोड़ की लागत से 67 कि.मी, राजसमंद में 70 करोड़ की लागत से 58 कि.मी, टोंक में 58.50 करोड़ की लागत से 25.43 कि.मी तथा उदयपुर में 65.25 करोड़ की लागत से 39 कि.मी राज्य सड़कों का सुदृढ ीकरण एवं चौड़ाईकरण करवाया जाएगा।

दिल्ली में कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने साफ किया कि चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में फैसला चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल द्वारा किया जाएगा।

बता दें कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन दोनों दल एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे। लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगे थे कि उनकी पार्टी दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी 70 में से 60 से ज्यादा सीटें जीती थी।

बिरसा मुण्डा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुंडा ने लिखा, 'धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा मेरे बड़े भाई आज 29.11.2024 की रात को लगभग 12:30 बजे हमारे बीच नहीं रहे।'

बता दें कि सड़क हादसे के बाद मंगल मुंडा को रांची स्थित रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उनका जारी था। इसके बाद मंगल मुंडा के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ट्रॉमा सेंटर एंड सेंट्रल इमरजेंसी में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंगल मुंडा के परिजनों से भी बात की और डॉक्टरों से कहा कि मंगल मुंडा का बेहतर इलाज किया जाए साथ ही उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लम्बित अपराधिक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत ने करीब नौ माह पहले याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।

जनहित याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी ने अदालत को बताया कि अलवर में करीब दस हजार वर्ग मीटर जमीन का स्कूल के लिए आवंटन वोकेशनल एजुकेशन ट्रस्ट को हुआ था। ट्रस्ट ने यू.आई.टी. में आवेदन कर इसका विभाजन करा लिया और एक हिस्सा पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल की पार्टनरशिप वाली फर्म दिव्या इन्फोटेक को बेच दिया। वहीं, फर्म ने यहां मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए मंजूरी मांग ली। याचिका में कहा गया कि स्कूल के लिए आवंटित भूमि का दूसरा उपयोग नहीं जा सकता।

इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने कहा कि अदालत को याचिका की मेरिट पर जाने से पहले याचिकाकर्ताओं का आचरण देखना चाहिए। एक याचिकाकर्ता नीलेश खंडेलवाल ने वर्ष 2014 में सिंघल के खिलाफ एम.एल.ए. का चुनाव लड़ा था और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जबकि अन्य याचिकाकर्ता हेमंत कुमार व अन्य के खिलाफ भी आपराधिक मामले हैं। जनहित याचिका की आड़ में ब्लैकमेलिंग, राजनीतिक हित और व्यक्तिगत हित साधे जा रहे हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका को हर्जाने के साथ खारिज कर दिया है।

महाराष्ट्र में बस पलटने से नौ की मृत्यु

- एक दुपहिया वाहन को ओवर टेक करते हुए बस पलट कर 20 फुट नीचे गड्ढे में गिर गई।
- दुर्घटना में घायल 25 यात्रियों में से कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिंदे ने मृतकों के परिजनों को दस लाख रु. की आर्थिक सहायता के निर्देश दिये।

गोंदिया, 29 नवंबर। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के दाववा गांव के पास शुक्रवार दोपहर महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम (एम.एस.आर.टी.सी.) की एक बस पलट जाने से नौ यात्रियों की मौत हो गई और अन्य 25 घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, हादसा तब हुआ, जब एम.एस.आर.टी.सी. की शिव शाही बस भंडारा से गोंदिया जा रही थी। बस दोपहिया वाहन को ओवरटेक करने के दौरान पलटकर सड़क से करीब 20 फुट नीचे गहरे गड्ढे में गिर गयी। इसमें सवार नौ यात्रियों की मौत हो गई, अन्य 25 यात्री घायल हो गए, जिसमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

बस दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद, दाववा के ग्रामीण दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। 108 एंबुलेंस बुलाई गई और उन्हें गोंदिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

हादसे की जानकारी मिलते ही डुग्गीपार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। हादसे के कारण गोंदिया-कोहमारा मार्ग पर यातायात कुछ देर के लिए रोक दिया गया।

कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कलेक्टर प्रजीत नायर से हादसे की जानकारी ली। प्रशासन को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

शिंदे ने मृतक के परिजनों को दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया।

प्रशासन ने सम्भल में इंटरनेट चालू किया

लखनऊ, 29 नवंबर। संभल में बवाल के बाद इंटरनेट पर लगे बैन को हटा लिया गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल होने से लोगों को राहत मिली है। इस बीच संभल जिला प्रशासन ने किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने पर पाबंदी लगा दी है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए, जिले में पुलिस बल को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है।

जानकारी के अनुसार, संभल जिला प्रसाशन ने अगले 10 दिनों तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के आने पर रोक लगा दी है। यह रोक पहले 30 नवंबर तक थी, जिसे अब अगले 10 दिनों तक और बढ़ा दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि अगले 10 दिन के बाद स्थिति को देखते हुए इस संबंध में फैसला लिया जाएगा।

वहीं, समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर को संभल जायेगा और पीड़ित लोगों से मिलकर रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को देगा। प्रतिनिधिमंडल में कई सांसद और विधायक भी शामिल हैं। सपा से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पाण्डेय के नेतृत्व में 15 सदस्य प्रतिनिधिमंडल संभल का दौरा करेगा।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908